प्रेस विज्ञप्ति

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय
ने अपनी पहली 'स्टेट ऑफ वर्किंग इण्डिया' रिपोर्ट जारी की

अधिकांश क्षेत्रों में मेहनताना प्रति वर्ष लगभग 3% की दर से बढ़ा है, लेकिन 82% पुरुष और 92% महिलाएं प्रति माह 10,000 रुपये से कम कमाते हैं।

नई दिल्ली, 25 सितम्बर, 2018: अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय ने आज नई दिल्ली में अपनी पहली 'स्टेट ऑफ़ वर्किंग इंडिया' (SWI) रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट (CSE) वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध है।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय द्वारा इस पहल का उद्देश्य सभी के लिए नियमित आय के साथ सार्वभौमिक रोजगार प्राप्त करने के लिए नीतिगत उपायों का मार्गदर्शन करना है। सीएसई अपनी वेबसाइट के माध्यम से अनुसंधान और शिक्षण के लिए आसानी से सुलभ आँकड़े भी प्रदान करता है।

रिपोर्ट में पाया गया है कि ज्यादातर क्षेत्रों में मेहनताना बढ़ा है, हालांकि जाति और लैंगिक असमानताएं अभी भी अधिक है। मेहनताने की तुलना में श्रम उत्पादकता कई गुना तेजी से बढ़ी है। नतीजतन नियोक्ताओं ने मज़दूरों और कर्मचारियों की तुलना में कहीं अधिक लाभ कमाया है। रोजगार कम पैदा हुए हैं। भारत आर्थिक विकास की उच्च दर को अच्छी नौकरियों में बदलने के लिए जूझ रहा है, खासकर अपने शिक्षित युवाओं के लिए।

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अनुराग बेहार ने कहा कि, 'भारत के लिए अपने सभी नागरिकों हेतु न्यायसंगत और टिकाऊ आजीविका के अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय की 'स्टेट ऑफ वर्किंग इण्डिया' रिपोर्ट गहन शोध पर आधारित है। यह ऐसे कई मुद्दों की पड़ताल करती है जो देश में रोजगार वृद्धि को निष्पक्ष और पूर्ण समावेशन के साथ एक अभियान का रूप दे सकते हैं। हम इस रिपोर्ट को पहले चरण के रूप में देखते हैं - गहरे, निरंतर और जमीनी शोध के साथ। यह चरण अन्य संस्थानों और क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने एवं विस्तृत समझ विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा।'

अज़ीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के संकाय सदस्य एवं रिपोर्ट के मुख्य लेखक अमित बसोले ने इसमें जोड़ा कि रिपोर्ट पिछले कुछ वर्षों की नहीं बल्कि पिछले कई दशकों की उन संरचनात्मक समस्याओं का विश्लेषण करती है जिन्होंने पर्याप्त रोजगार पैदा होने में बाधा उत्पन्न की है।

रिर्पोट के कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं :

रोजगार के बिना वृद्धि : वर्तमान में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 7% की वृद्धि रोजगार में 1% से भी कम की वृद्धि में परिवर्तित होती है। यह विशेष रूप से शिक्षित युवाओं को प्रभावित करता है। युवाओं और उच्च शिक्षितों के बीच बेरोजगारी का दर 16% तक पहुँच गया है।

संगठित उद्योगों का पुनरुद्धार : पिछला दशक में संगठित औद्योगिक क्षेत्र का प्रदर्शन अच्छा रहा है। कई उद्योगों (विशेष तौर पर बड़े नियोक्ता जैसे बुने हुए कपड़े, प्लास्टिक और फुटवेअर) में मेहनताने और रोजगारों में वृद्धि हुई है। इसकी एक वजह यह है की १९८० और १९९० के दशकों के मुकाबले मज़दूरों के स्थान पर मशीनों के इस्तेमाल की प्रवृत्ति धीमी हुई है, शायद इस लिए की अब एक करोड़ रुपये के पूँजी निवेश (२०१५ के रुपये में) द्वारा केवल १० नौकरियां समर्थित होती हैं, एवं इस आंकड़े का और घटना मुश्किल हो गया है।

मेहनताने में वृद्धि : पिछले डेढ़ दशक में मेहनताने (मुद्रास्फीति के लिए समायोजित) में निरन्तर वृद्धि हुई है। कृषि को छोड़कर अधिकांश क्षेत्रों में वास्तविक मेहनताने में सालाना 3% या इससे ज्यादा की वृद्धि हुई है। हालाँकि मासिक आय कम ही बनी हुई है। 82% पुरुष और 92% महिला कामगारों का वेतन 10,000 रुपए प्रति माह से कम है। वास्तव में सभी क्षेत्रों में मेहनताना, सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित वेतन (18,000 रुपए प्रति माह) से काफी कम है। मेहनताने की तुलना में श्रमिक उत्पादकता कई गुना तेजी-से बढ़ी है। परिणामस्वरूप इस वृद्धि से नियोक्ताओं को श्रमिकों की तुलना में काफी ज्यादा फायदा हुआ है।

अनिश्चितता में वृद्धि : कार्य की अनिश्चितता बढ़ी है। स्थाई मज़दूरों की बजाय कम्पनियों ने विभिन्न प्रकार के अनुबन्धित और प्रशिक्षु मज़दूरों को काम पर लिया है, जो उसी कार्य को कम वेतन पर करते हैं।

लैंगिक व जातिगत असमानताएँ : लैंगिक व जातिगत असमानताएँ बहुत अधिक हैं। उदाहरण के लिए सभी सेवा क्षेत्र के कामगारों में 16% महिलाएँ हैं जबकि घरेलू कामगारों में 60% महिलाएँ हैं। इसी प्रकार, सभी कामगारों में 18.5% अनुसूचित जातियों से हैं जबकि चमड़े के कुल कामगारों में से 46% अनुसूचित जातियों से हैं। एक सकारात्मक बात यह है कि समय के साथ आय में लैंगिक अन्तर घट रहा है। भुगतान पाने वाले कार्यों में महिलाओं की भागीदारी अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। उदाहरण के लिए जहाँ उत्तर प्रदेश में प्रति 100 पुरुषों पर केवल 20 महिलाएँ भुगतान पाने वाले कार्यों में हैं वहीं तमिलनाडु में यह संख्या 50 और उत्तर-पूर्वी राज्यों में 70 है।

रिर्पोट में प्रस्तावित किया गया है कि केन्द्र सरकार को रज्यों के सहयोग के साथ निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए **राष्ट्रीय रोजगार नीति** बनाना चाहिए :

- दुनिया भर में रोजगार गारण्टी के विचार की लोकप्रियता बढ़ रही है। मनरेगा के साथ भारत इस ट्रेंड का अगुवा रहा है और इसके अनुभव के आधार पर इसे आगे बढ़ना चाहिए।

- वैश्विक स्तर पर औद्योगिक नीति में रुचि बढ़ी है और मेहनताना सब्सिडी व कुशल कामगारों का कौशल बढ़ाने वाली नई नीतियों का उदय हुआ है।

- सफल राज्य–स्तरीय रोजगार नीतियों का विश्लेषण करने और राज्य के अनुभवों की विविधता से सीखने की जरूरत है।

- सार्वजनिक निवेश के लिए इस्तेमाल की जाने वाली राजकोषीय गुजांइश (fiscal space) पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषि में आय के स्तर को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है और इस हेतु सार्वजनिक निवेश ज़रूरी है।

- यूनीवर्सल बेसिक सर्विसेस (UBS) प्रोग्राम बनाने पर सर्कार विचार करे। नौकरियों, मानव पूंजी और सार्वजनिक सेवाएं बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, सार्वजनिक परिवहन एवं सुरक्षा में निवेश करे।

रिपोर्ट का दूसरा खंड बैकग्राउंड पेपर्स के साथ जल्द ही प्रकाशित होगा।

About Azim Premji University

Azim Premji University was established as a not-for-profit, private university under the Azim Premji University Act 2010. The University has a clear social purpose of working towards a just, equitable, humane and sustainable society. Azim Premji University plays a critical role in developing new talent, building capacity in existing functionaries and creating domain knowledge in the fields of education and in development. The Azim Premji Foundation is the sponsor of the University. The roots of Azim Premji University lie in the learning and experience of a decade of work in elementary education by Azim Premji Foundation. The University is one of the Foundation's key responses to the challenges confronting the education and development sectors in India.

For media queries contact:

Sachin Mulay – sachin.mulay@apu.edu.in | +91 9845329164

Shreya Basu - Shreya.basu@k2communications.in | + 91 74320 57950